

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	<p>पौष 18, शुक्रवार, शके 1942-जनवरी 08, 2021 Pausa 18, Friday, Saka 1942-January 08, 2021</p>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2020

संख्या प.10(216) कृषि/गुप-2/1974 :-चूंकि राजस्थान सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु निम्नांकित भूमि अर्जन का आशय रखती है।

अतः राजस्थान सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित भूमि अर्जन के सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु **Center For Development Communication & Studies (CDECS) 133 Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road Sodala, Jaipur 302019 Rajasthan (INDIA)** को नियुक्त करती है। उपरोक्त एजेन्सी/संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।

- परियोजना विकासकर्ता का नाम-कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़
- प्रस्तावित परियोजना-कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण का विस्तार।
- अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विवरण-

क्र.स.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	रकबा	भूमि का वर्ग	भूमि का स्वामित्वाधिकार
1	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	769	0.62	बी-I अडान- I	श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह
2	"	"	"	770	0.14	बी-I	"
3	"	"	"	771	0.01	धामनी	"
4	"	"	"	772	1.21	अडान- I बी-I धामनी	4"
5	"	"	"	773	0.13	धामनी	"

4. परियोजना क्षेत्र- प्रतापगढ़ जिले में मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण विस्तार के लिए नगर परिषद् क्षेत्र में मन्दिर श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह की भूमि 2.11 हैक्टर।
5. प्रभावित क्षेत्र- प्रतापगढ़ में मण्डी प्रांगण के विस्तार परियोजना में श्री रामचन्द्रजी स्थान देह की 2.11 हैक्टर भूमि का अवाप्त किया जाने वाला क्षेत्र है।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य-
 - (a) प्रभावित संबंधित पक्ष को समुचित प्रतिकर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनका समुचित पुनर्वास एवं पुनर्ब्यवस्थापन सुनिश्चित करना।
 - (b) भूमि अवाप्ति से संभावित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की पहचान करना और ऑनसाइट क्षेत्र की जांच, जन सुनवाई और परामर्श के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करना।
 - (c) भूमि अवाप्ति से संभावित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को प्रभावित व्यक्तियों के साथ साझा करना तथा सकारात्मक प्रभावों में अभिवृद्धि करना तथा नकारात्मक प्रभावों की तीव्रता को कम करना।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप-
 - (i) परामर्श
 - (ii) सर्वेक्षण
 - (iii) सार्वजनिक सुनवाई
8. ग्राम सभा या नगरपालिका या यथास्थिति नगरनिगम और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है- हां
9. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रारंभ दिनांक- अधिसूचना जारी होने की दिनांक से
10. सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण होने की समय सीमा- अधिसूचना जारी होने की तारीख से 06 माह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।
11. सामाजिक समाघात निर्धारण के अन्तिम प्रदेय-
 - (i) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
 - (ii) सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना
12. सामाजिक समाघात निर्धारण के अन्तिम प्रदेय पंचायत या यथास्थिति नगरपालिका, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के कार्यालयों में तथा कृषि विपणन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
13. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के दौरान प्रपीड़न या धमकी का कोई प्रयास कार्यवाही को अकृत और शून्य बना देगा।
14. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई सम्पर्क सूचना-

Dr. Upendra K.Singh

CEO Cum Member Secretary (Mob-9950124028)

Center For Development Communication & Studies (CDECS)

133 Devi Nagar, Nannu Marg, New Sanganer Road Sodala,
Jaipur 302019
Rajasthan (INDIA)
Email-cdecjsjpr@gmail.com

राज्यपाल की आज्ञा से,
बृज गुप्ता,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।